

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 16 फरवरी, 2019 / 27 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 फरवरी, 2019

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी.—एफ(4)3/2018.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.—बी.—एफ(4)1/2015, तारीख 2 दिसंबर, 2016 और 27 मई, 2017 की विधिमान्यता की समाप्ति के परिणामस्वरूप, भारत के संविधान से संलग्न पाँचवीं अनुसूची के खण्ड 5 के उप—खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि वन (संरक्षण) अधिनियम,

1980, हिमाचल प्रदेश नौतोड रूल्ज, 1968 के कार्यान्वयन के सीमित प्रयोजन और अनिवार्य विकास क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होगा,—

- क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क / अभ्यारण्य / आरक्षित संरक्षण / आरिक्षत समुदाय / आरिक्षत वन / सीमांकित संरक्षित वन में नहीं आता हो।
- नौतोड़ के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3. जहां—कहीं इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नौतोड़ भूमि पहले ही मंजूर कर दी गई है, परन्तु पट्टे प्रदान नहीं किए जा सके थे, पट्टे अब उसी स्थान के लिए प्रदान किए जा सकेंगे जहां के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। असीमांकित संरक्षित वनों (यू पी एफज) में नौतोड़ की नई मंजूरियों के लिए, भूमि के टुकड़े ऐसी रीति में चिन्हित किए जाएं, कि सामान्य वन और क्षेत्र की पारिस्थितिकी अस्त—व्यस्त न हों। इसलिए वनों में नौतोड़ के अलग—अलग आबंटन के परिवर्जन के आशय से भूमि के टुकड़ों की पहचान राजस्व और वन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाए। संबन्धित वन मण्डल अधिकारी को असीमांकित संरक्षित वन क्षेत्रों में नौतोड़ के आबंटन के लिए ऐसे समय तक जब तक कि अनुसूचित क्षेत्रों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू नहीं हो जाता है, निराक्षेप प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।
- 4. इस प्रकार प्रदत्त नौतोड़ का उपयोग केवल वास्तविक घरेलू प्रयोजन के लिए किया जाएगा और यह किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 5. नौतोड़ किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी, जो वन भूमि पर अतिक्रमण सहित किसी प्रकार के वन अपराध में सम्मिलित हो।
- 6. कोई वन भूमि, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, जिसमें प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है।
- 7. कोई वन भूमि, जिसमें रास्ते और सड़कें विद्यमान हैं, जो स्थानीय निवासियों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, किसी भी प्रयोजन के लिए प्रदान नहीं की जाएगी।
- 8. सरकार द्वारा व्यवस्थित करवाए जाने वाले आवश्यक विकासात्मक क्रियाकलापों के अन्तर्गत (1) स्कूल, (2) औषधालय/अस्पताल, (3) विद्युत और दूरसंचार लाइनें, (4) पेयजल परियोजनाएं, (5) जल/वर्षा जल संग्रहण अवसंरचना, (6) लघु सिंचाई नहरें, (7) नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत, (8) कौशल उन्नयन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, (9) विद्युत सब—स्टेशन, (10) संचार चौकियां, (11) सड़क किनारे स्थापनों के पहुंच—मार्गी सिंहत, सड़कों का सिन्नर्माण/चौड़ा करना (12) सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा विद्यमान पुलों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना, (13) गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापनाएं जैसे कि पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/सीमा आउटपोस्ट/निगरानी टावर। इन क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञा वन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अलग—अलग मामलों के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एफ.एफ.ई.—बी.—एफ(4)1/2015, तारीख 31 दिसम्बर, 2016 द्वारा पहले ही विरचित विनियम के अनुसार अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया और प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्रदान की जाएगी।

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(4)3/2018 dated 13-02-2019 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

#### FORESTS DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 13th February, 2019

**No. FFE-B-F(4)-3/2018.**—Consequent upon expiry of validity of the Government of Himachal Pradesh Notification No. FFE-B-F(4)1/2015, dated 2nd December, 2016 and 27th May, 2017, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under sub-clause (1) of clause 5 of FIFTH SCHEDULE appended to the Constitution of India, is pleased to direct that the Forest (Conservation) Act, 1980 shall not apply to the Scheduled Areas of the State of Himachal Pradesh for the limited purpose of implementation of the Himachal Pradesh Nautor Rules, 1968 and carrying essential development activities, for a period of one year, subject to fulfilment of the following conditions,—

- 1. The area does not fall in National Park/Sanctuary/Conservation Reserve/Community Reserve/Reserve Forest/Demarcated Protected Forest.
- 2. The number of trees standing over the land proposed to be allowed as Nautor should not exceed two.
- 3. Where ever Nautor land has already been sanctioned by competent authority till the date of issue of the this Notification but *pattas* could not be granted, *pattas* may now be granted at the same location for which sanction was issued. For new sanctions of Nautor in Un-demarcated Protected Forests (UPFs), land parcels be selected in such a manner that the general forests and ecology of the area is not disturbed. Land chunks be therefore identified jointly by Revenue and Forest officers in order to avoid scattered allotment of Nautor in the Forests. Divisional Forest Officer concerned shall be authorized to issue No Objection Certificate for allotment of Nautor in Un-demarcated Protected Forests areas till such time as Forest (Conservation) Act, 1980 does not apply in the Scheduled Areas.
- 4. The Nautor so granted is utilized only for bonafide domestic purpose and is not utilized for any commercial activity.
- 5. The Nautor is not granted to any such person who is involved in any kind of forest offence including encroachment on forest land.
- 6. No forest land shall be granted for any purpose in which natural water resources are utilized by the local inhabitants.
- 7. No forest land will be granted for any purpose where paths and roads exist which are used by the local inhabitants.
- 8. The essential developmental activities to be provided by the Government shall include (1) Schools, (2) Dispensaries/Hospitals, (3) Electric and Telecommunication lines, (4) Drinking water projects, (5) Water/Rain Water Harvesting Structures, (6) Minor Irrigation Canals, (7) Renewable Sources of Energy, (8) Skill Upgradation/Vocational Training Centres, (9) Power sub-stations, (10) Communication

posts, (11) Construction/Widening of roads including approach roads to road side establishments, (12) Upgradation/ Strengthening/Widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO), (13) Police Establishments like Police Stations/ Outposts/Border Outposts/watch towers in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs. Permission for these activities shall be granted by the Forest Department, Government of Himachal Pradesh, on case to case basis as per the regulation already framed by the Government of Himachal Pradesh *vide* Government of Himachal Pradesh letter No. FFE-B-F(4)-1/2015, dated 31st December, 2016, specifying procedure and authorities for granting the permission.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

[Authoritative English text of this Government Notification No. Rev.D(F)4-2/2000-V, dated 4-2-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

# **REVENUE DEPARTMENT** (Disaster Management Cell)

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 4<sup>th</sup> February, 2019

**No. Rev.** (DMC)(F)4-2/2000.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (2) of Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 and in supersession of this department notification of even No. dated 1-06-2007 and 21-05-2014, the Chairperson of Himachal Pradesh State Disaster Management Authority is pleased to nominate the following persons as members of the Himachal Pradesh State Disaster Management Authority:—

- (1) Chief Secretary, Chief Executive Officer, ex-officio
- (2) ACS/Principal Secretary/Secretary (Revenue)
- (3) ACS/Principal Secretary/Secretary (Home)
- (4) ACS/Principal Secretary/Secretary (PWD)
- (5) ACS/Principal Secretary/Secretary (IPH)
- (6) ACS/Principal Secretary/Secretary (Health)
- (7) Director General of Police, Himachal Pradesh
- (8) Special/Additional/Joint Secretary (Rev.-DM), Member Secretary

By order

MANISHA NANDA, *Additional Chief Secretary (Revenue).* 

#### लोक निर्माण विभाग

# अधिसूचना

#### शिमला-2, 7 फरवरी, 2019

सं0पी0बी0डब्ल्यू०(बी0)एफ(5)7/2018.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल पुईद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में रामिशला बिजली महादेव सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

- 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा—11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
- 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
- 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपित हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अविध के भीतर लिखित रूप में भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपित दायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकबा (है0 में)
कुल्लू	कुल्लू	पुईद	210	0-02-35
			243	0-04-05
			242	0-03-71
			278	0-00-16
			284	0-01-61
			285	0-02-86
			287	0-02-39
			291	0-01-90
			149	0-00-75
			148	0-01-38
			147	0-01-40
			146	0-00-14
			145	0-01-11
			387	0-01-35

	386	0-02-13
	391	0-01-89
	390	0-01-40
	389	0-01-88
	406	0-01-44
	404	0-06-32
	कित्ता 20	0-40-22

आदेश द्वारा, मनीषा नंदा, अति० मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

\_\_\_\_\_

## HOME DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 15th February, 2019

**No. Home-B-A(1)4/2007.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to establish three (03) Family Courts in the State of H.P. alongwith their respective jurisdiction as under:—

Sl. No.	Name of Court	Jurisdiction (District)
1.	Family Court, Shimla	Shimla, Solan, Sirmour and Kinnaur
2.	Family Court, Mandi	Mandi, Kullu, Lahaul & Spiti and Bilaspur
3.	Family Court, Kangra at Dharamshala	Kangra, Chamba, Una and Hamirpur

1. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to create following posts for each of these Courts, alongwith their mode of recruitment/appointment as under:—

Sl. No.	Name of post	Number of Post	Mode of Filling Up
1.	Distt. & Sessions Judge	01	By Regular appointment
2.	Superintendent Gr-II	01	By promotion
3.	Reader Gr-I	01	By promotion
4.	Stenographer Gr-I	01	By promotion
5.	Judgment Writer	01	Direct recruitment on contract basis
6.	Nazir	01	Direct recruitment on contract basis
7.	Clerk-cum-typist	01	Direct recruitment on contract basis

8.	Cr. Ahlmad	01	Direct recruitment on contract basis
9.	Civil Ahlmad	01	Direct recruitment on contract basis
10.	Driver	01	Daily wage basis
11.	Orderly	01	Daily Wage basis
12.	Peon	01	Daily Wage basis
	Total	12	

**Note.**—The Services of Chowkidar and Sweeper for each of these courts shall be hired only on outsource basis.

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

# ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री फरन्गो, निवासी गांव लाहड, डाकघर बैली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जोगिन्दर सिंह है। आधारा कार्ड व परिवार नकल ग्राम पंचायत बैली में मेरा सही नाम जोगिन्दर सिंह दर्ज है। लेकिन मेरी मलकीयती भूमि महाल लाहड, पटवार वृत्त बैली में मेरा नाम योगिन्दर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–03–2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

प्रकाश सिंह नरयाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

## ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री प्यार पुत्र सुखदेव, निवासी गांव गुहाला, डाकघर राड़ी, मुहाल व परगना राड़ी, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम प्यार सिंह पुत्र सुखदेव है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल राड़ी में प्यार चन्द पुत्र सुखदेव दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्यार चन्द पुत्र सुखदेव के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26—02—2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप–तहसील धरवाला. जिला चम्बा. हि० प्र०।

\_\_\_\_\_

# In the Court of Sh. Sandeep Sood, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer (c), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

- 1. Sanjeev Kumar s/o Sh. Yog Raj, r/o Village Khatarwar, P.O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
- 2. Manorama Devi d/o Sh. Kamlesh Kumar, r/o Village Darkoti, P.O. and Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).

Versus

#### General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sanjeev Kumar s/o Sh. Yog Raj, r/o Village Khatarwar, P.O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Manorama Devi d/o Sh. Kamlesh Kumar, r/o Village Darkoti, P.O. and Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the

Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 14-12-2018 at Mata Awahdevi Mandir, Awahdevi as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-03-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-01-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

> Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

# ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बडसर, उप-मण्डल बडसर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

- Vinod Kumar Age 34 years s/o Sh. Nikka Ram, r/o Village & P.O. Bhakreri, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
- Ramna Devi Age 19 years d/o Sh. Devi Singh, r/o Village Koyal Gadej, P.O. Koyal, प्रार्थी । Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.)

बनाम

प्रतिवादी। आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 25-03-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / – विवाह पंजीकरण अधिकारी,

बडसर, उप-मण्डल बडसर, जिला हमीरपर (हि0 प्र0)।

# ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 05 / 18 / टी0

तारीख पेशी : 28-02-2019

श्रीमती ओमां देवी पत्नी मदन लाल, वासी महाल कस्बा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा :—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल उग्राहला उपरला, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

श्रीमती ओमां देवी पत्नी मदन लाल, वासी महाल कस्बा, महाल जखधार, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसका सही नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख व आधार कार्ड व महाल कस्बा के राजस्व अभिलेख में ओमां देवी पत्नी मदन लाल दर्ज है जो कि सही है परन्तु महाल उग्राहला उपरला, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम उषा देवी पत्नी मदन लाल दर्ज है जो कि सही न है। प्रार्थिया ने उक्त नाम की दरुस्ती बारे अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 28—02—2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें अन्यथा गैर—हाजिरी की सूरत में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर या एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 22-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

# In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi, H. P.

In the matter of:—

- 1. Arun aged 25 years s/o Shri Joginder Singh, r/o Baldora, P. O. Ghar Jarot, Tehsil Jawali, District Kangra, H. P.
- 2. Kajal Kapoor aged 22 years d/o Shri Kapoor Chand, r/o H. No. 239/10, Changar Colony, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. presently w/o Arun s/o Shri Joginder Singh, r/o Baldora, P. O. Ghar Jarot, Tehsil Jawali, District Kangra, H. P. . . . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

#### NOTICE:

Arun and Kajal Kapoor have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-11-2018 according to Hindu custom and rites and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-02-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30-01-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-Marriage Officer-cum-SDM, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

# In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No.: ..../ 2019 Date of Instt.: 01-02-2019 Pending for: 30-03-2019

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

#### **Notice to the General Public:**

Whereas, Shri Ravi Sharma (D.O.B. 23-01-1987) s/o Shri Anand Lal, r/o Village Behrota, P.O. and Tehsil Ramshehar, District Solan (H.P.) and Smt. Alyssa Juliette Castaneda (D.O.B. 09-09-1992) d/o Shri Kenneth Castaneda, r/o 650 County Road, 125 Sidney, TX 76474 presently w/o Shri Ravi Sharma s/o Shri Anand Lal, r/o Village Behrota, P.O. and Tehsil Ramshehar, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 29-11-2018;

And, whereas, both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that both were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 30-03-2019

for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 30-03-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 01-02-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM, Nalagarh, District Solan (H. P.).

# ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप—तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)

(नोटिस: जेरे आदेश 5, नियम 20, सी०पी०सी०)

श्री जोगिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार / नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री ईशर दास, निवासी गांव पोलियांबीत, डाकघर पोलियांबीत, सब—तहसील दुलैहड़, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती विशो देवी की मृत्यु गांव व डाकघर पोलियांबीत में दिनांक 23—06—2000 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उनकी मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 22—02—2019 को प्रातः दस बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर / एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24–01–2019 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।